

शारीरिक दंड

प्रलिस के लयः

[राषट्रीय बाल अधकार संरक्षण आयोग, कशोर नयाय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) अधनियम, 2015, शकषा का अधकार अधनियम, 2009](#)

मेन्स के लयः

शारीरिक दंड का मुद्दा, शारीरिक दंड के संबंघ में संवैधानक और कानूनी प्रावधान ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तमलनाडु स्कूल शकषा वभाग ने स्कूलों में शारीरिक दंड के उन्मूलन (GCEP) के लयि दशानरदेश जारी कयि ।

- ये दशानरदेश छात्रों के शारीरिक एवं मानसक हतों की सुरक्षा पर केंद्रति हैं एवं वदियार्थयों के कसी भी प्रकार के उत्पीडन को रोकने करने के लयि शारीरिक दंड को समाप्त करते हैं ।

दशानरदेशों के मुख्य बदि क्या हैं?

- इन दशानरदेशों का उद्देश्य शारीरिक दंड, मानसक उत्पीडन एवं भेदभाव को समाप्त कर वदियार्थयों के लयि सुरक्षति एवं वकिसपूर्ण वातावरण नरिमति करना है ।
- GCEP में वदियार्थयों के मानसक स्वास्थय की सुरक्षा करना एवं हतिधारकों को [राषट्रीय बाल अधकार संरक्षण आयोग \(NCPCR\)](#) के दशानरदेशों से परचिति कराने के लयि जागरूकता शविरि आयोजति करना भी सम्मलति है ।
- GCEP दशानरदेशों के कार्यानवयन की नगरानी और कसी भी मुद्दे का समाधान करने हेतु प्रत्येक स्कूल में स्कूल प्राचार्यों, अभभावकों, शकषकों एवं वरषिठ वदियार्थयों को सम्मलति करते हुए [नगरानी समतियों की स्थापना](#) पर जोर देता है ।
- GCEP ने शारीरिक दंड के वरिद्ध सकारात्मक कारवाइयों को भी सूचीबद्ध कयि है, जसमें बहु-वषयक हस्तक्षेप, जीवन-कौशल शकषा एवं बच्चों की शकियतों के लयि तंत्र शामिल हैं ।

शारीरिक दंड क्या है?

- परचयः
 - बाल अधकारों पर संयुक्त राषट्र समति द्वारा शारीरिक दंड को परभाषति कयि गया है, "कोई भी दंड जसमें शारीरिक बल का उपयोग कयि जाता है और बच्चों के लयि कुछ हद तक दर्द अथवा परेशानी उत्पन्न करने का इरादा होता है, चाहे वह दंड कतिना भी सरल क्यों न हो ।"
 - समतिके अनुसार, इसमें ज्यादातर बच्चों को हाथ या डंडे, बेल्ट आदि से मारना (पीटना, थपपड मारना) सम्मलति है ।
 - [वशिव स्वास्थय संगठन \(WHO\)](#) के अनुसार, शारीरिक या शारीरिक दंड वैश्वक स्तर पर घरों तथा स्कूलों दोनों में अत्यधिक प्रचलति है ।
 - 2 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के लगभग 60% बच्चे नयिमति रूप से अपने माता-पति या अन्य देखभाल करने वालों द्वारा शारीरिक रूप से दंडति कयि जाते हैं ।
 - भारत में बच्चों के लयि 'शारीरिक दंड' की कोई वैधानक परभाषा नहीं है ।
- शारीरिक दंड के प्रकारः
 - [राषट्रीय बाल अधकार संरक्षण आयोग \(NCPCR\)](#) द्वारा परभाषति शारीरिक दंड में कोई भी ऐसा कार्य शामिल है जो कसी बच्चे को दर्द, चोट या हानि पहुँचाता है ।

- इसमें बच्चों को बेंच पर खड़ा करना, दीवार के सामने कुरसी जैसी मुद्रा में खड़ा करना या सरि पर स्कूल बैग लेकर बैठने जैसी असुवधाजनक स्थितियों में मजबूर करना सम्मिलित है।
- इसमें पैरों में हाथ डालकर कान पकड़ना, घुटनों के बल बैठना, **जबरन पदार्थ खलाना** एवं बच्चों को स्कूल परिसर के भीतर बंद स्थानों तक सीमित रखना जैसी प्रथाएँ भी शामिल हैं।
- **मानसिक उत्पीड़न का** संबंध गैर-शारीरिक दुरव्यवहार से है जो **बच्चों के शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण** पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- दंड के इस रूप में **व्यंग्य, अपशब्दों तथा अपमानजनक भाषा का उपयोग करके डाँटना, डराना और अपमानजनक टिप्पणियों का उपयोग** जैसे व्यवहार शामिल हैं।
- इसमें बच्चे का उपहास करना, उसका अपमान करना या उसे लज्जित करना, भावनात्मक कष्ट और समस्याग्रस्त वातावरण नरिमति करना जैसे कार्य भी शामिल हैं।
- **शारीरिक दंड का औचित्य:**
 - वर्तमान में अमेरिका के 22 राज्यों में स्कूलों में शारीरिक दंड की वधिक अनुमति है।
 - **भारतीय दण्ड संहिता (IPC), 1860** की कुछ धाराएँ शारीरिक दंड हेतु आधार प्रदान करती हैं।
 - धारा 88 "किसी व्यक्ति के लाभ के लिये सद्भावना से सहमति से किये गए **कृत्यों** के लिये सुरक्षा प्रदान करती है, जो मृत्यु का कारण नहीं है।"
 - धारा 89 किसी अभिभावक द्वारा या उसकी सहमति से किसी बच्चे या वक्षिपित व्यक्ति के **लाभ के लिये सद्भावना से किये गए कार्यों** की रक्षा करती है।
 - कशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: शब्द "बच्चे का सर्वोत्तम हित" धारा 2(9) को संदर्भित करता है, जिसमें कहा गया है कि नरिणय लेते समय बच्चे की पहचान, शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास, साथ ही उनके बुनियादी अधिकारों एवं ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिये, जिसका उन पर प्रभाव पड़ता है।
- **शारीरिक दंड के प्रभाव:**
 - **मानसिक स्वास्थ्य:**
 - बढ़ी हुई चिंता तथा अवसाद: शारीरिक दंड के कारण बच्चे असुरक्षित, डरा हुआ व वातावरण को अरुचिपूर्ण अनुभव कर सकते हैं। इससे उनमें मानसिक चिंता एवं अवसाद बढ़ सकता है तथा आगे चलकर शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो सकता है।
 - आत्मसम्मान में कमी: जनि बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से दंडित किया जाता है उनमें कम आत्मसम्मान और आत्म-मूल्य की नकारात्मक भावना विकसित हो सकती है।
 - **आकरामकता एवं हिसा:** जो बच्चे हसिक कृत्यों को देखते हैं उनके बड़े होकर **आकरामक या हसिक होने की संभावना** अधिक होती है। बच्चा अपने सहपाठियों और शिक्षक के प्रति प्रतिशोध की भावना भी विकसित कर सकता है।
 - **संबंधों में कठिनाई:** जो बच्चे शारीरिक दंड का अनुभव करते हैं उन्हें दूसरों के साथ व्यावहारिक संबंध बनाने में कठिनाई हो सकती है।
 - **शारीरिक स्वास्थ्य:**
 - **शारीरिक चोट:** मामूली चोटों से लेकर अधिक गंभीर चोटों तक शारीरिक क्षति शारीरिक दंड के कारण हो सकती है।
 - **मादक द्रव्यों का सेवन:** जो बच्चे शारीरिक दंड का अनुभव करते हैं, वे वयस्कों की तरह ड्रग्स और शराब का दुरुपयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं।

शारीरिक दंड के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या हैं?

- **वैधानिक प्रावधान:**
 - **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009:**
 - अधिनियम की धारा 17 **शारीरिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध** लगाती है। यह 'शारीरिक दंड' और 'मानसिक उत्पीड़न' पर रोक लगाती है तथा इसे **दंडनीय अपराध** बनाती है।
 - यह **नरिदषिट करती है** कि उल्लंघन करने वाले पक्ष को उन पर लागू होने वाले सेवा नयिमों के अनुरूप **अनुशासनात्मक कार्रवाई** का सामना करना पड़ेगा।
 - **कशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:**
 - इस अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार, किसी **नाबालगि का प्रभारी वयस्क** जो जानबूझकर नाबालगि को त्यागकर, दुरव्यवहार करके, या उसकी उपेक्षा करके मानसिक अथवा शारीरिक हानि पहुँचाता है, उसे **अधिकतम 6 माह की जेल की सज़ा** और जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
- **कानूनी प्रावधान:**
 - **भारतीय दण्ड संहिता (IPC) 1860**
 - धारा 305 एक बच्चे को आत्महत्या के लिये उकसाने से संबंधित है

- धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुँचाने से संबंधित है
- धारा 325 जो स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने के बारे में है।

■ न्यायिक मामले:

- अंबिका एस नागल [?] [?] [?] [?] हिमाचल प्रदेश राज्य, 2020 में, राज्य उच्च न्यायालय ने माना कि "जब भी किसी बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, तो माता-पिता ने अपने बच्चे को सज़ा और अनुशासन के अधीन होने पर एक नहिती सहमत देने के लिये कहा होगा।"
- केरल राज्य के खिलाफ एक मामले में, 2014 में केरल उच्च न्यायालय ने राजन बनाम पुलसि के उप-नरीक्षक शीर्षक से शारीरिक दंड देने को बरकरार रखते हुए कहा कि यह उन मामलों में भी बच्चों के लिये लाभदायक था, जहाँ परणाम अत्यधिक थे, क्योंकि शिक्षक के पास यह नरिणय करने का अधिकार है कि उसे दंड देना है अथवा नहीं।

■ बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 21 A: 6-14 आयु वर्ग में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
- अनुच्छेद 24: यह 14 वर्ष की आयु तक जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
- अनुच्छेद 39 (e): यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि आर्थिक असमानता के कारण कम उम्र के बच्चों के साथ दुरव्यवहार न हो।
- अनुच्छेद 45: 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।
- अनुच्छेद 51A(k): माता-पिता का मौलिक कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि उनके बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के लिये शिक्षा प्राप्त हो।

■ सांविधिक निकाय:

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights- NCPCR): बच्चों के खिलाफ शारीरिक दंड को समाप्त करने के लिये NCPCR दशान्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्कूल को छात्रों की शिकायतों को दूर करने हेतु एक प्रभावी तंत्र विकसित करने और उचित प्रोटोकॉल स्थापित करने की आवश्यकता है।
 - प्रत्येक स्कूल को एक 'शारीरिक दंड नगिरानी सेल' का गठन करना होगा जिसमें दो शिक्षक, दो माता-पिता, एक डॉक्टर और एक वकील (ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित (District Legal Service Authority- DLSA) शामिल होंगे।

■ अंतरराष्ट्रीय कानून:

- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1989 (UNCRC) के अनुच्छेद 19 में घोषणा की गई है कि हिसा से जुड़े किसी भी प्रकार का अनुशासन अस्वीकार्य है।
- इसमें बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट और दुरव्यवहार से बचाने का अधिकार है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है?

- NCPCR एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी।
- यह आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान एवं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में नहिती बाल अधिकारों के परिरक्षण के अनुरूप हों।
- यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत बच्चों के लिये मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है।
- यह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences- POCSO) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन की नगिरानी करता है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए शारीरिक दंड के मुद्दे पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]:

प्रश्न: मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का नमिनलखिति में से कौन-सा/से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 (Universal Declaration of Human Rights, 1948) के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता/करते है/हैं? (2020)

1. उद्देशिका
2. राज्य के नीतिनिदेशक
3. मूल कर्तव्य

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2011)

1. शकिषा का अधकिर
2. सार्वजनकि सेवा तक समान पहुँच का अधकिर
3. भोजन का अधकिर

उपर्युक्त में से कौन-सा/से "मानव अधकिरों की सार्वभौम घोषणा" के अंतर्गत मानवाधकिर है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. यद्यपि मानवाधकिर आयोगों ने भारत में मानव अधकिरों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फरि भी वे ताकतवर और प्रभावशालयिों के वरिद्ध अधकिर जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारकि सीमाओं का वशिलेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजयि। (2021)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/corporal-punishment>

